inter-alia violation of the provisions of Sections 159, 209, 120, 211, 220, 224, 225, 229 and 301 of the Companies Act, 1956 and a copy of the investigation report has been forwarded to the Regional Director, Calcutta, for further necessary action in the matter.

Scheme to attract NRI investment in real estate

580. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the scheme to attract NRI investigation in real estate covering housing and commercial constrtuction is pending with his Ministry for clearance;

(b) if so, since when it is pending with his Ministry;

(c) the reasons for which it is pending and whether Government propose to clear it; and

(d) if so, by when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

लोक अदालतों का कार्यकरण

581. **श्री राघव जी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से गत तीन वर्षों से किन-किन राज्यों में लोक अदालतों के प्रयोग चल रहे हैं;

(ख) उक्त तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने मामलों का निराकरण किया गया; और

(ग) क्या सरकार की कोई ऐसी पद्धति अपनाने की योजना है जिससे छोटे-छोटे मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो सके ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) कलैंडर वर्ष, 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी में लोक अदालतें आयोजित की गई हैं।

(ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या
1989	4,12,455
1990	6,42,462
1991	1,32,255

(ग) लोक अदालत, जो समझा-बुझाकर और सुलह के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए स्वैच्छिक प्रयास है, न्यायालय के बाहर मामलों के शीघ्र निपटारे का प्रभावी तंत्र साबित हुई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना

582. **श्री राघव जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं उसकी खंडपीठों में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं;